



सत्यमेव जयते

File No: P2/1316/2025
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA),
MADHYA PRADESH)



Dated: 16/01/2026



To,

Kapil Agrawal
J K CEMENT LIMITED
JK Cement Limited, Kamla Tower, Kanpur Uttar Pradesh 208001, Kanpur, KANPUR NAGAR,
UTTAR PRADESH, , 208001
bhaskar.rawat@jkcement.com

Subject: Grant of EC under the provision of the EIA Notification 2006-regarding.

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Grant of EC under the provision of the EIA Notification 2006-regarding in respect of project "Construction of the Residential Colony with a Plot Area of 14 Ha and a Built-up Area of 34,050 sq.m at Villages- Sotipura & Harduaken, Tehsil Amanganj, District Panna (M.P.) by JK Cement Works Panna (A unit of JK Cement Limited)." submitted to Ministry vide proposal number SIA/MP/INFRA2/523297/2025 dated 09/04/2025.

2. The particulars of the proposal are as below:

(i) EC Identification No.	EC25C3801MP5670992N
(ii) File No.	P2/1316/2025
(iii) Clearance Type	EC
(iv) Category	B2
(v) Project/Activity Included Schedule No.	8(a) Building / Construction "Construction of the Residential Colony with a Plot Area of 14 Ha and a Built-up Area of 34,050 sq.m at Villages- Sotipura & Harduaken, Tehsil Amanganj, District Panna (M.P.) by JK Cement Works Panna (A unit of JK Cement Limited)."
(vii) Name of Project	
(viii) Name of Company/Organization	J K CEMENT LIMITED
(ix) Location of Project (District, State)	PANNA, MADHYA PRADESH
(x) Issuing Authority	SEIAA
(xi) Applicability of General Conditions	no
(xii) Applicability of Specific Conditions	no



Ref.:Proposal No.: SIA/MP/INFRA2/523297/2025, Case No.: P2/1316/2025
Prior Environment Clearance for Construction of the Residential Colony with a Plot Area of 140000 sq.m (14 Ha.) and a Built-up Area of 34,050 sq. m. at Villages- Sotipura & Harduaken, Tehsil Amanganj, District Panna (M.P.) by Shri Kapil Agrawal, Unit Head, J. K. Cement Limited, Kamla Tower, Kanpur (U.P.) Pin - 208001.

With reference to above the proposal has been appraised as per prescribed procedure & provisions under the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O. 1533 (E), dated 14th September 2006 and its amendment, on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz., Form (CAF, Part A B & C) , Form IA, Conceptual Plan, drawings and subsequently submission of EIA/ EMP report, PPT& the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority.

1. उक्त परियोजना आवासीय कॉलोनी ग्राम-सोतीपुरा एवं हरदुआकेन, तहसील अमानगंज, जिला पन्ना (म.प्र.) में स्थित है, जिसमें कुल प्लॉट क्षेत्रफल 14 हेक्टेयर तथा कुल निर्मित क्षेत्र 34,050 वर्गमीटर में श्री कपिल अग्रवाल, यूनिट हेड, जे.के. सीमेन्ट लिमिटेड, कमला टॉवर, कानपुर (उ.प्र.)-208001 द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्रफल 1,40,000 वर्ग मीटर, तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल 34,050 वर्ग मीटर (मौजूदा क्षेत्रफल 16,620 वर्ग मीटर + प्रस्तावित क्षेत्रफल 17,430 वर्ग मीटर) है जो 1,50,000.00 sq.m से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावित परियोजना आवासीय उपयोग के अंतर्गत है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 838वी बैठक दिनांक 25-10-2025 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 9 से 23 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :-

SN	Information Required	Details
1.	Project Name/Activity	Shri Kapil Agrawal, Unit Head, J K Cement Limited, Kamla Tower, Kanpur (U.P.) Pin - 208001. <i>Prior Environment Clearance for Construction of the Residential Colony with a Plot Area of 140000 sq.m (14 Ha.) and a Built-up Area of 34,050 sq.m at Villages- Sotipura & Harduaken, Tehsil Amanganj, District Panna (M.P.) by J K Cement Limited." Cat. - 8(a). Building and Construction Projects.</i>
2.	Project Cost.	7700 Lakhs.

3.	Description of Project	The proposed residential project is situated at Villages- Sotipura & Harduaken, Tehsil Amanganj, District Panna (M.P.) with a Plot Area of 14 Ha and a Built-up Area of 34,050 sq.m with 198 units along with the Director's Bungalow, Unit Head's Bungalow, Guest House & Bachelor Hostel, Commercial & Retail Spaces etc. by JK Cement Ltd.
4.	Gram Panchayat NoC	Gram Panchayat Devara Janpad Panchayat Pawai Distt. - Panna (M.P.) Dated 02/10/2019
5.	CGWA NOC Status	<ul style="list-style-type: none"> Project Name: J K Cement Limited, Harduaken, Puraina, Sotipura And Madaiyan, Block: Pawai, Distt. - Panna (M.P.). NOC No: CGWA/NOC/IND/REN/2/2024/10402. Application No.: 21-4/863/MP/IND/2019. Date of Issuance: 30/12/2024. Valid from: 31/01/2025. Valid up to: 30/01/2028.
6.	NOC Forest	Distance PTR APCCF_Panna Cement Plant.
7.	Nagar Parisad NOC	Amanganj Letter No. 594 dated 18/01/2024.
8.	Parking	Existing - 200 ECS Proposed - 280 ECS Total - 480 ECS.
9.	CTE /Consent detail	PCB ID: 159558 Consent No:AW- 60376, Consent valid up to 30/04/2029.
10.	Environmental Consultant details	Shri Vipul Khandelwal. Director & Coordinator M/s Gaurang Environmental Solutions Pvt. Ltd., Jaipur, (Rajasthan). Valid up to 07/12/2026.

Project Summary:

S.No	Items	Details		
1.	Project Name	Construction of the Residential Colony with a Plot Area of 14 Ha and a Built-up Area of 34,050 sq.m at Villages- Sotipura & Harduaken, Tehsil Amanganj, and District Panna (M.P.) by JK Cement Limited		
2.	Location	Villages, Sotipura & Harduaken, Tehsil Amanganj, and District Panna (M.P.)		
3.	Type of Project	Expansion of Residential Colony		
4.	Project details	Existing as per CTE	Proposed	Total
5.	Total Plot area	140000sq.m	No change	140000sq.m
6.	Project cost	Rs.37Crores	Rs.40Crores	Rs.77Crores
7.	Gross Built up area	16620 sq.m	17430 sq.m	34050 sq.m
a.	FAR Area	12542 sq.m.	12972 sq.m.	25,514sq.m.
b.	Non-FAR Area	4078 sq.m.	4458 sq.m.	8536 sq.m.
8.	Green Area	14100 sq.m (10.07%)	No Change	14100 sq.m (10.07%)

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)की 838वी बैठक दिनांक 25.10.2025 की, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)की 924वीं बैठक दिनांक 23.12.2025 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्न बिंदु i से viii को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

A. Specific Conditions as recommended by SEIAA

- i. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदासी होगी।
- ii. परियोजना के जलापूर्ति के लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।
- iii. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- iv. परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यों में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
- v. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30% गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO₂ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।
- vi. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।
- vii. परियोजना स्थल पर ई-वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- viii. प्रस्तावित भवन में संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन-धन हानि न हो।

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें (भवन व निर्माण के प्रकरणों हेतु)

परिशिष्ट -1

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :-

- a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदनुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
- c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
2. भूमि स्वामित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनामति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।
5. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network
9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.
10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.

11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.
12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.
13. For firefighting:-
- PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. arrangement should be made available on the project. All the required fire fighting .2016 site as per NBC
 - The occupancy permit shall be issued by Municipal Corporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.
 - Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises
14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.
15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.
16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping
17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.
18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.
19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.
20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.
21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, GoI notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.
23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June

and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - <http://www.environmentclearance.nic.in/> or <http://www.efclearance.nic.in/> and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also

25. The Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report, Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, Gol at Bhopal and MPPCB.
26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.
27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.
28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.
29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely, SRM, RSPM, SO₂, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.
30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.
31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at

www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal.

33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

B. Specific Conditions as recommended by SEAC

I. Statutory Compliance

- i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
- ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
- iii. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
- iv. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- v. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, and Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
- vi. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
- vii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.
- viii. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low lying area. The top soil shall be used for greenery development.

II. Air Quality Monitoring and preservation

- i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for

Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.

- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
- iv. The source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
- v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
- vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
- vii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- viii. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
- ix. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
- x. The source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height

of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.

- xi. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest-rain water.
- ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.
- iii. The total water requirement during operation phase is 297 KLD out of which 175 KLD is fresh water requirement and 122 KLD will be the total recycled water generated and the same will be used for flushing (54 KLD) and 68 KLD water will be used for horticulture.
- iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.
- v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
- vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.
- vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled

- water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
- ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
- xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
- xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fire water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.
- xiii. For rainwater harvesting, 11 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about 75 m³/hr. Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.
- xiv. The RWH will be initially done only from the roof top.
- xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.
- xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
- xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water

balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.

- xix. Sewage shall be treated in the MBBR or equivalent based STP (Capacity - 145 KLD). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.
- xx. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 145 KLD capacity (based on MBBR or equivalent technology) and then reuse for various purposes. No water body or drainage channels should be affected in the study area because of this project.
- xxi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP
- xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. Noise monitoring and prevention

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.
- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures

- i. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- ii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design.
- iii. Energy Conservation measures like installation of CFLs/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
- iv. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level /local building bye-laws requirement, which is higher.
- v. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. Waste Management

- i. Total waste 481 Kg/day, this consist all types of wastes (as Organic waste 289 Kg/day and non- organic waste 192 Kg/day and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules-2016.
- ii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.
- iii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- iv. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (0.4 ton/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.
- v. All non-biodegradable waste shall be handed over to the authorized recyclers.

- vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
- ix. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly c, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.
- vii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016. Ready mixed concrete must be used in building construction.
- viii. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.
- ix. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. Green Cover

- i. Total 1750 trees shall be planted in the area of 14,100 sq.m (10.07% of total plot area) which is developed as greenbelt development as follows:

S.No.	Scientific Name	Local Name
1.	<i>Azadirachta indica</i>	Neem
2.	<i>Pongamia glabra</i>	Indian Beech
3.	<i>Dalbergia sisoo</i>	Shisham
4.	<i>Terminalia arjuna</i>	Arjun
5.	<i>Aegle marmelos</i>	Bael
6.	<i>Millingtonia hortensis</i>	Neem Chameli
7.	<i>Pithecellobium dulce</i>	Jungal Jalebi
8.	<i>Syzygium cumini</i>	Jamun
9.	<i>Delonix regia</i>	Gulmohar
10.	<i>Cassia samia</i>	Kassod
11.	<i>Neolamarckia cadamba</i>	Kadamba

12.	<i>Callistemon lanceolatus</i>	Bottlebrush Tree
13.	<i>Bauhinia blakeana</i>	Kachnar (Red-flowered bauhinia)
14.	<i>Albizia lebbek</i>	Siris
15.	<i>Grevillea robusta</i>	Silver Oak
18.	<i>Ficus religiosa</i>	Peepal Tree
19.	<i>Ficus infectoria</i>	White Fig
20.	<i>Ficus benghalensis</i>	Banyan Tree
21.	<i>Plumeria alba</i>	Champa
22.	<i>Peltophorum pterocarpum</i>	Peela gulmohar
23.	<i>Bombax ceiba</i>	Semal
24.	<i>Chukrasia tabularis</i>	Chikrasi

Approx.1895 nos. of tree saplings of mentioned species have already been planted at the site.

- ii. No tree will be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolute necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (Planted).
- iii. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land shall be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should included plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
- iv. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.
- v. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII. Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
 - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
 - b. Traffic calming measures.
 - c. Proper design of entry and exit points
 - d. Parking norms as per local regulation
- ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
- iii. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

- iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. EMP & Corporation Environment Responsibility

- i. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide E.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.
- iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported

to the Ministry/Regional Office along with the Six -Monthly Compliance Report.

- v. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 617.0 lakhs as capital and Rs.13.0 lakhs as recurring cost for this project during construction and operation phase.
- vi. Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018 was suppressed by the OM dated 30.09.202. However, the for this project, the PP has proposed Rs.77.0 Lakhs as Corporate Environment Responsibility (CER) for various activities as below:

S. No.	Particulars	Activity	Time bound (year wise) expenditure (in Rs. Lakhs)			Total Rs. Lakhs
			1 Year Rs. Lakhs	2 Year Rs. Lakhs	3 Year Rs. Lakhs	
1.	Education	Infrastructure development including separate toilets for male and female students in Govt. Sr. Sec. School, Village Tighera, Tehsil Amanganj, District Panna (M.P.)	1	1	0	2.00
		Infrastructure development including rain water harvesting system.	3	3	0	6.00
		Infrastructure development including Smart Class Rooms in Govt. Sr. Sec. School, Village Tighera, Tehsil Amanganj, District Panna (M.P.)	5	5	5	15.00
		Infrastructure development including light fitting at Government Senior Secondary School, Village Tighera, Tehsil Amanganj,	0.50	0.50	-	1.00

		District Panna (M.P.)				
		Infrastructure development including Solar panel 5Kw. in Govt. Sr. Sec. School, Village Tighera, Tehsil Amanganj, District Panna (M.P.)	3	-	-	3.00
2.	Plantation (Ek Ped Maa Ke Naam-2024)	Plantation will be done on the road side with tree guards in Village Tighera, Puraina, Deora Tehsil Amanganj, District Panna (M.P.) .	5	5	5	15.00
3.	Community infrastructure	Infrastructure development including construction of a Community Hall at Village Tighera, Tehsil Amanganj, District Panna (M.P.) .	10	10	10	30.00
3.	Health & sanitation	A medical and health check-up camp will be organised at Village Tighera, Puraina, Deora Tehsil Amanganj, District Panna (M.P.) .	2	2	1	5.00
GRAND TOTAL			29.50	26.50	21.00	77.00

XI. Miscellaneous

- i. The PP shall not construct residential colony in the north - east direction of the cement plant as per EC issued by MOEF&CC for cement plant also no residential/accommodation shall be set up in the plant area. The issuance of this EC recommendation in no way relax the any

condition/suggestion mentioned under EC issued by MOEFCC for cement, mine for the existing plant.

- ii. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board, local Administration in various clearance and the State Government.
- iii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
- iv. No further expansion or modification in the colony shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- v. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- vi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

(Deepak Arya)
Member Secretary

Copy to -

- (1). Principal Secretary, Department of Environment., Government of MP, Mantralaya Vallabh Bhawan, Bhopal.
- (2). Member Secretary, SEAC, Research and Development Wing Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony Bhopal-462016.
- (3). Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016.
- (4). The Collector, District Panna -M.P.
- (5). Chief Municipal Officer (CMO) Nagar Palika Parishad, District Panna -M.P.
- (6). The Assistant Director, Town & Country Planning Department, Panna (M.P.)
- (7). MP Real Estate Regulatory Authority, 1, Main Rd, Zone-I, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh 462011
- (8). Director, I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF, GoI, Ministry of Environment & Forest Indira Paryavaran Bhawan, JorBagh Road, New Delhi - 110 003

(9). Director (S), Regional office of the MOEF, (Western Region), Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3, Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016.

(10). Guard file.

Member Secretary

